भारतीय रिजर्व बैंक की तिमाही मौद्रिक नीति समीक्षा

प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं

लगातार तीन महीनों से मुद्रास्फीति की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत के मुकाबले 4.7 प्रतिशत तक सुधरने और उद्योग की सभी श्रेणियों खासतौर पर खनन में गिरावट के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी रेपो दर और नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

मध्य तिमाही मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने विनिर्माण गतिविधियों में "तत्काल परिवर्तन" का उल्लेख करते हुए वृद्धि में तेजी लाने की जिम्मेदारी सरकार पर डाली है। शीर्ष बैंक का कहना है कि "निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर निवेश में तेजी लाने अथवा निजी निवेश, परियोजना मंजूरी में सुधार और सार्वजनिक निवेश के क्रियान्वयन और उससे प्राप्त लाभ विकास की कुंजी है।"

मुख्य बिंदु

- प्रमुख लघु अवधि ऋण ब्याज दर (रेपो दर) को 7.25 पर बरकरार रखा गया
- नकद आरक्षी अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं है और पहले की तरह ही यह चार प्रतिशत है।
- रूपए में आई गिरावट, बाह्य क्षेत्र जोखिम और खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि चिंता का कारण।
- आरबीआई ने वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार को निजी निवेश के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करने और परियोजना मंजूरी में तेजी लाने को कहा।
- मुद्रास्फीति में टिकाऊ गिरावट से मौद्रिक नीति योजना तय करने का मार्ग सुगम होगा।
- चालू खाता घाटा एक चुनौती है, इसको कम करने के लिए आरबीआई ने स्थिर विदेशी प्रवाह की वकालत की।
- 2013-14 में चालू खाता घाटे को कम करने के लिए सोने के आयात को सीमित करने और वस्तुओं की कीमतों में कमी लाने के लिए कदम।
- भविष्य की मौद्रिक अवस्थिति तय करने के लिए भुगतान, मुद्रास्फीति और वृद्धि दर में संतुलन
- वैश्विक अस्थिरता और पूंजी प्रवाह पर इसके प्रभाव के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता।
- बाह्य क्षेत्र में किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई सभी उपलब्ध उपकरणों के इस्तेमाल के लिए तैयार।
- सकारात्मक रेटिंग से निवेशकों के भरोसे में वृद्धि होनी चाहिए।

प्रमुख अवधारणाएं

- रेपो दर- वह दर जिसपर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है।
- रिवर्स रेपो दर- वह दर जिसपर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती है।
- नकद आरक्षी अनुपात- आरबीआई के पास बैंकों द्वारा रखे जाने वाली निर्धारित आवश्यक पूंजी

यह स्पष्ट करते हुए कि वृद्धि में रुकावट में ब्याज दरों की कोई भूमिका नहीं है आरबीआई ने आगे यह उल्लेख किया कि बुनियादी ढांचे में रूकावट, आपूर्ति बाधा, मांग में कमी और निवेश माहौल के अनुकूल न होने की वजह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। आरबीआई ने कहा कि मुद्रास्फीति में सुधार हुआ है लेकिन परोक्ष मुद्रास्फीति, रूपए के कमजोर पड़ने और खाद्य मुद्रास्फीति के जारी रहने के कारण खतरा बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि वैश्विक बाजार की संवेदना में तेजी से बदलाव का जोखिम भी है जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं से यकायक रूकावट तथा पूंजी के विपरीत रूख का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

(मुख्य संपादक अनुराग मिश्रा द्वारा संकलित)